साप्ताहिक
जागत गांव हमार
पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक
RNI-MPHIN/2015/72544
चौपाल से भोपाल तक
भोपाल, सोमवार, 5-12 जनवरी 2025 वर्ष-10, अंक-38
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित
पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

तकनीशियन नहीं होने से 16.24 करोड़ रुपए की लागत से तैयार प्रयोगशालाएं बंद, लेकिन खरीदी चालू

कृषि मंत्री ने कहा-स्टॉफ की भर्ती के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा

बुंदेलखंड की 28 मिट्टी परीक्षण लैब में छह साल से लटक रहा ताला, फिर भी 87 लाख का भेज दिया गया केमिकल

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड के पांच जिलों में 28 मिट्टी परीक्षण लैब ऐसी है, जो 6 साल से बंद पड़ी है। बावजूद इसके इन मिनी लैब में 87.21 लाख रुपए का केमिकल भेज दिया। ये केमिकल 4 महीने से ऐसा ही पड़ा है, जो अप्रैल 2025 में एक्सपायर हो जाएगा। तकनीशियन नहीं होने से इन लैबों के अभी चालू होने की उम्मीद भी नहीं है। केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत साल 2017-18 में मध्यप्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में मृदा परीक्षण केंद्र खोलने के लिए राशि जारी की। इसके तहत बुंदेलखंड के 5 जिलों में 28 केंद्रों का निर्माण हुआ। एक मिनी लैब का भवन 36 लाख में तैयार हुआ। इस तरह 10.08 करोड़ रुपए खर्च किए। फिर इन सभी केंद्रों में कम्प्यूटर और लैब उपकरण स्थापित किए। इस पर 22 लाख रुपए प्रति मिनी लैब खर्च किए। इसका कुल खर्च 6.16 करोड़ आया। इस प्रकार बुंदेलखंड की 28 लैब पर 16.24 करोड़ खर्च किए। अब इन लैबों में स्टॉफ पदस्थ करना था, लेकिन प्रदेश सरकार ने ये काम नहीं किया। नतीजतन इनमें से एक भी लैब चालू नहीं हो पाई। अब कृषि विभाग ने इन सभी लैब के लिए केमिकल भेज दिया है, जो अनुपयोगी हो रहा है।

छतरपुर में 52 लाख रुपए का केमिकल आया

सागरः जिले में 11 लैब है, इसमें से 10 लैब बंद पड़ी है। इन 10 लैब के लिए 45 बॉक्स केमिकल आया है। प्रत्येक बॉक्स की कीमत 65 हजार रुपए है। कुल 29.25 लाख रुपए का केमिकल आया है।

छतरपुरः जिले में 8 लैब है, इसमें से 7 लैब बंद पड़ी है। इन 7 लैब के लिए 80 बॉक्स केमिकल आया। प्रत्येक बॉक्स की कीमत 65 हजार रुपए है। कुल 52 लाख रुपए का केमिकल आया है।

दमोहः जिले में सात लैब है, इसमें छह लैब बंद पड़ी है। इन 6 लैब के लिए 14 किट केमिकल आया। प्रत्येक किट की कीमत 14 हजार रुपए है। कुल 1.96 लाख रुपए का केमिकल आया।

टीकमगढ़ः जिले में 4 लैब है, इसमें 3 बंद है। इन 3 लैब के लिए 10 किट केमिकल आया। एक किट की कीमत 20 हजार रुपए है। कुल 2 लाख का केमिकल आया।

निवाड़ीः जिले में 2 लैब है, दोनों बंद हैं।

सागरः रहली की मिट्टी परीक्षण लैब का भवन ही जर्जर हो गया| ये है सागर जिले के रहली में स्थित मिनी लैब भवन। छह साल में लैब का भवन ही जर्जर हो गया। पानी के पाइप टूट गए हैं। खिड़कियों के कांच भी तोड़ दिए हैं। भवन का चैनल खुला पड़ा है। इसके लिए आई मशीनें भी धूल खा रही है।

दमोहः शिलालेख टूट गए लेकिन इस प्रयोगशाला का ताला नहीं खुला| दमोह जिले के बटियागढ़ की इस मिनी लैब का शिलालेख ही टूट गया लेकिन ताला नहीं खुला। यहां भी लैब के लिए 22 लाख रुपए की लागत से आए कम्प्यूटर और उपकरण स्टोर रूम में धूल खा रहे हैं। स्टॉफ अब तक पदस्थ नहीं किया।

सरकार जांच कराएगी

सागर संभाग की बंद मिनी लैबों के लिए केमिकल भेजा गया है। लैब बंद है तो केमिकल भेजना ही नहीं चाहिए था। यह गलत है। इसकी जांच करवाएंगे कि ऐसा क्यों किया गया। प्रदेश में मिट्टी परीक्षण लैब स्टॉफ की कमी की वजह से बंद है। इनमें स्टॉफ की भर्ती के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा है।

एंदल सिंह कंषाना, कृषि मंत्री मप्र

केंद्रीय कैबिनेटः मोदी सरकार ने दी 24475 करोड़ की सब्सिडी

खरीफ की तरह रबी फसलों के लिए एमएसपी में बड़ी वृद्धि की गई

रबी सीजन में सस्ते रेट पर मिलेगी खाद

भोपाल। जागत गांव हमार

रबी सीजन में किसानों को खाद सस्ते रेट पर मिलेगी। इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट ने गैर-यूरिया खाद की सब्सिडी का ऐलान कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में इस सब्सिडी का ऐलान किया गया। सरकार ने रबी सीजन के लिए 24,475 करोड़ रुपए की सब्सिडी का निर्णय लिया है। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। इसके अलावा, कैबिनेट ने गेहूं की एमएसपी 150 रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया। कैबिनेट ने 2025-26 रबी मार्केटिंग सीजन के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 6.59 प्रतिशत बढ़ाकर 2,425 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया। महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली जैसे राज्यों में चुनावों से पहले गेहूं के समर्थन मूल्य में 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी अहम है। रबी सीजन अप्रैल 2025 से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2025-26 रबी सीजन के लिए छह अनिवार्य रबी फसलों के एमएसपी में 130-300 रुपए प्रति क्विंटल की सीमा में वृद्धि को मंजूरी दी।

कैबिनेट का फैसला

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट द्वारा लिया गया प्रमुख निर्णय किसानों के कल्याण से जुड़ा है। खरीफ की तरह रबी फसलों के लिए एमएसपी में बड़ी वृद्धि की गई है। गेहूं का समर्थन मूल्य पिछले वर्ष के 2,275 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2025-26 के लिए 2,425 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तिलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए, कैबिनेट ने 2025-26 रबी सीजन के लिए रेपसीड/सरसों के समर्थन मूल्य को 300 बढ़ाकर 5,950प्रति क्विंटल कर दिया।

चना 5,650 रुपए क्विंटल

कुसुम का समर्थन मूल्य पिछले वर्ष के 5,800 प्रति क्विंटल से 140 रुपए बढ़ाकर 5,940 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। दालों के मामले में, मसूर का समर्थन मूल्य 275 बढ़ाकर 6,700 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया, जबकि 2025-26 के रबी सीजन के लिए चने का एमएसपी 210 बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। 2025-26 के रबी सीजन के लिए जौ का समर्थन मूल्य 130 बढ़ाकर 1,980 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया, जो पिछले वर्ष 1,850 रुपए प्रति क्विंटल था।

सरकार की घोषणा

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के हिसाब से है, जिसमें एमएसपी को उत्पादन की औसत लागत से कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर तय करने की घोषणा की गई थी। उत्पादन की औसत लागत पर मार्जिन गेहूं के लिए 105 प्रतिशत है, इसके बाद रेपसीड और सरसों के लिए 98 प्रतिशत, मसूर के लिए 89 प्रतिशत, चने के लिए 60 प्रतिशत, जौ के लिए 60 प्रतिशत और कुसुम के लिए 50 प्रतिशत है। मंत्री ने कहा कि रबी फसलों के एमएसपी में की गई वृद्धि से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा और फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज बोले- बिगड़ते पर्यावरण से धरती संकट में

सावधान! अगर इसी तरह पर्यावरण बिगड़ता रहा तो धरती पर जीवन मुश्किल होगा

भारत की 960 लाख हेक्टेयर जमीन बंजर

भोपाल। जागत गांव हमार

देश की 960 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन बंजर हो चुकी है। मिट्टी में मौजूद जैविक तत्वों में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। जबकि, पानी के तेज बहाव और हवा के चलते हर साल कई टन टॉप सॉइल नष्ट हो रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज धरती संकट में है। अगर पर्यावरण इसी तरह बिगड़ता रहा तो ये सवाल खड़ा हो गया है कि धरती रहने लायक बचेगी। केवल मानव जाति नहीं जीव-जंतु के अस्तित्व पर भी संकट पैदा हो जाएगा। शिवराज ने दिल्ली में कहा कि आज जरूरी है कि हम पर्यावरण बचाने का अभियान चलाएं। जिसका सशक्त माध्यम है कि वृक्षारोपण। मेरे मन में संकल्प पैदा हुआ कि मैं खुद रोज पेड़ लगाऊं। पेड़ लगाना मेरी दिनचर्या का अभिन्न अंग है। 19 फरवरी 2021 के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने पेड़ ना लगाया हो, कोविड के दौरान भी मैंने इसे जारी रखा। इससे पहले एक संबोधन में उन्होंने बताया कि देश की 30 फीसदी जमीन खराब हो चुकी है। इधर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. एम मुरुगानंदम ने कहा कि भारत विश्व के कुल भूमि क्षेत्र का 2.4 फीसदी है। यह 17.7 फीसदी वैश्विक जनसंख्या और 15 फीसदी पशुधन का पोषण करता है। हालांकि, देश की मिट्टी तेज कृषि, शहरीकरण, वन कटाई और जलवायु परिवर्तन के चलते अत्यधिक दबाव में है। इसरो की हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि भारत की 960 लाख हेक्टेयर भूमि खराब हो चुकी है। इतना ही नहीं, हर साल 5.3 अरब टन टॉपसॉइल पानी और हवा के तेज बहाव के चलते नष्ट हो जाती है।

केमिकल इस्तेमाल से बचना होगा

वैज्ञानिकों ने मिट्टी के स्वास्थ्य को बरकारर रखने केमिकल का इस्तेमाल नहीं करने और क्षरण रोकने का आह्वान किया है। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान मुख्यालय और देशभर में अपने 8 अनुसंधान केंद्रों के साथ हाल ही में एक कोर रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और मृदा स्वास्थ्य का आकलन करना है। इससे मिट्टी में हो रहे बदलावों की पहचान कर सुधार के लिए उपायों को लागू करना है। वैज्ञानिकों ने मिट्टी के स्वास्थ्य को बरकारर रखने के लिए केमिकल का इस्तेमाल नहीं करने और क्षरण रोकने के लिए पौधारोपण करना होगा।

-किसानों को दलहन-तिलहन उत्पादन के लिए भी करें प्रोत्साहित

दलहन-तिलहन में भी मप्र होगा नंबर वन

-मुख्यमंत्री ने कहा-उद्यानिकी फसलों का उत्पादन भी बढ़ाया जाए

-किसानों को उपार्जन के बाद भुगतान भी जल्द से जल्द किया जाए

-सीएम ने प्रदेश में जारी सोयाबीन उपार्जन की समीक्षा में दिए निर्देश

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश में सोयाबीन फसल उत्पादन में बीते वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार सोयाबीन का उपार्जन जारी रखेगी। सोयाबीन के अलावा किसानों को दलहन और तिलहन फसलों के उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। किसानों के साथ चर्चा कर योजना बनाई जाएगी। उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में अधिक लाभ है, इसलिए किसानों को उद्यानिकी फसलों के लिए जागरुक किया जाए। यह बात सीएम डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में सोयाबीन उपार्जन की समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सभी सोयाबीन उत्पादक किसानों से उपार्जन कर उन्हें जल्द से जल्द भुगतान भी सुनिश्चित किया जाए। उपार्जन में किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई या बारदाने की समस्या न आने पाए। उपार्जित सोयाबीन का उठाव और भंडारण विधिवत तरीके से हो और उपज को ओला-पाला एवं बारिश से बचाया जाए।

छह लाख मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदी का अनुमान

बैठक में सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने सीएम को जानकारी दी कि प्रदेश में सोयाबीन उपार्जन 25 अक्टूबर से किया जा रहा है, जो 31 दिसंबर तक चला। उन्होंने सीएम को बताया कि 26 दिसम्बर तक 2 लाख 4 हजार किसान अपना सोयाबीन बेच चुके हैं। इन किसानों से 5 लाख 89 हजार मीट्रिक टन सोयाबीन उपार्जित किया गया है। 31 दिसंबर तक साढ़े 6 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन उपार्जन का अनुमान है। आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं।

सोयाबीन खरीदी में भोपाल संभाग अव्वल

बैठक में सीएम को बताया गया कि प्रदेश में भोपाल संभाग में सर्वाधिक 180198.04 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन उपार्जित किया गया है। उज्जैन संभाग में 149974.54 लाख मीट्रिक टन, सागर संभाग में 93495.33 लाख मीट्रिक टन और नर्मदापुरम संभाग में 93287.44 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन उपार्जित किया गया हैं। सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4 हजार 892 रुपए प्रति क्विंटल है। किसानों को 1957.1 करोड़ उपार्जन राशि का भुगतान अब तक किया जा चुका है।

नीलगाय भगाने का अचूक तरीका, भारी नुकसान से बचा रहा ये देसी फंडा

इधर, रबी सीजन की प्रमुख फसलें गेहूं, मक्का, चना, मटर, सरसों और आलू खेतों में बोई जा चुकी है। कई फसलें अब बड़ी होने लगी है, लेकिन इस बीच किसान को खेतों में अपनी खड़ी फसलों को लेकर चिंता में है, क्योंकि नीलगाय और जंगली जानवर फसल को खा जा रहे हैं और कुचल कर बर्बाद कर रहे हैं। इससे किसानों के हजारों रुपये की लागत और कड़ी मेहनत से तैयार होती फसल बर्बाद हो रही है। इनसे बचने के लिए किसान अपने खेतों में कई उपाय भी करते हैं। ऐसा ही एक देसी उपाय है जिससे फसलों को एक साथ तीन फायदे होंगे। सर्दियों के मौसम में खेतों में गेहूं, चना, मटर, मक्का सहित अन्य सब्जियों की खेती काफी ज्यादा होती है। ऐसे में हर किसान को जानवरों से फसल बचाने के लिए मुफ्त के कुछ उपाय करने चाहिए। इस उपाय में चूल्हे की राख किसानों के बहुत काम आ सकती है। दरअसल, इस समय किसान ठंड से बचने के लिए अपने घर में आग जलाते हैं और कुछ लोगों के घर में तो खाना भी चूल्हे पर बनता है, जहां से लकड़ी जलने के बाद राख मिल जाती है। उस राख को अच्छे से ठंडा करके उसे गेहूं चना मटर मक्का और सब्जियो की फसल में छिड़क दें। राख का स्वाद नीलगाय को पसंद नहीं आता, इससे वह एक पत्ती मुंह में डालने के बाद वापस खेत से लौट जाती है और दोबारा उसे खेत में नहीं आती है। राख डालने से सिर्फ नीलगाय खेत से दूर ही नहीं रहेंगी, बल्कि फसल की भी अच्छी पैदावार होगी। मतलब साफ शब्दों में कहें तो एक पंत दो काज यानी राख को फसल पर डालने से जानवर उसे नहीं खाएंगे, इसके अलावा फसलों पर पाला भी नहीं पड़ेगा। साथ ही राख खाद और कीटनाशक का भी काम करती है। नीलगाय के आतंक से बचने के लिए किसान घरेलू और आसान टिप्स को अपना सकते हैं।

-मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने किया एलान

युवा अन्नदूत योजना में अब होगा 14 लाख रुएक का किया जाएगा बीमा

भोपाल। जागत गांव हमार

युवा अन्नदूत योजना के अनुबंधित परिवहनकर्ता हितग्राहियों को 3064 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 14 लाख रुपये का बीमा कराया जाएगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि इस योजना के हितग्राहियों की असामयिक मृत्यु पर कोई सहायता नहीं प्राप्त होने से परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था। मंत्री राजपूत ने बताया कि हितग्राहियों के बीमा के लिए तीन बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। इनमें से पहली सामूहिक बीमा योजना का क्रियान्वयन फरवरी-2025 से होगा। इसका वार्षिक प्रीमियम 2608 रुपये और बीमित राशि 10 लाख रुपए है। वहीं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का क्रियान्वयन जून-2025 से होगा। इसका वार्षिक प्रीमियम 436 रुपये और बीमित राशि दो लाख रुपए है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का क्रियान्वयन जून-2025 से होगा। इसका वार्षिक प्रीमियम 20 रुपए और बीमित राशि दो लाख रुपए है।

कब मिलेगा बीमा का लाभ

योजना में पालिसी जारी होने की दिनांक से हितग्राही की दुर्घटना में मृत्यु होने पर पूरी बीमा राशि मिलेगी। पालिसी जारी होने की दिनांक से 30 दिन के बाद हितग्राही की अन्य कारण से (दुर्घटना को छोड़कर) मृत्यु होने पर पूरी बीमा राशि दी जाएगी। अन्य कारणों से 30 दिन में मृत्यु होने पर हितग्राही द्वारा देय प्रीमियम राशि का 80 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। बीमा पालिसी जारी होने के एक वर्ष की अवधि में आत्महत्या करने पर जीवन बीमा की राशि देय नहीं होगी, मात्र देय प्रीमियम राशि का 80 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। हितग्राही की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए। जीवन बीमा एक वर्ष के लिए होगा, जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराना होगा। हितग्राही की मृत्यु पर बीमा राशि परिवार को दी जाएगी।

इन अधिकारियों को मिला उच्च पद का प्रभार

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की पहल पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में कार्यरत अधिकारियों को उच्च पद का प्रभार दिया गया है। विभाग के 65 कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को वर्तमान पद स्थापना वाले जिले में ही उच्च पद का प्रभार देकर सहायक आपूर्ति अधिकारी का प्रभार सौंपा गया है। वहीं, नौ नापतौल निरीक्षकों को प्रभारी सहायक नियंत्रक नापतौल, एक सहायक नियंत्रक नापतौल को प्रभारी उप नियंत्रक नापतौल, एक उप नियंत्रक नापतौल को प्रभारी संयुक्त नियंत्रक नापतौल, नौ सहायक आपूर्ति अधिकारी प्रभारी को प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी और आठ जिला आपूर्ति अधिकारी को प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक बनाया गया है।

-आम-केला, अंगूर-सेब और सब्जियों की पैदावार आंकड़े

बागवानी फसलों का क्षेत्रफल बढ़ा पर उपज घटने का जताया अनुमान

भोपाल। जागत गांव हमार

बागवानी फसलों के क्षेत्रफल में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है, जबकि उत्पादन होने का अनुमान जताया गया है। 2023-24 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार आम, केला अंगूर उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी, जबकि सेब, अमरूद, अनार और अनानास का उत्पादन घटने की बात कही गई है। इसके अलावा सब्जियों में टमाटर, फूलगोभी, लौकी, गाजर समेत कुछ अन्य के उत्पादन में इजाफा होगा, जबकि आलू, प्याज, बैंगन और शिमला मिर्च समेत अन्य सब्जियों की उपज कम रहने की आशंका जताई गई है। वहीं, फलों, शहद, फूलों, मसालों और सुगंधित-औषधीय पौधों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी का अनुमान जताया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन का 2023-24 का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार बागवानी फसलों का कुल क्षेत्रफल 2023-24 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 280.98 लाख हेक्टेयर रहने वाला है। जो बीते साल 2022-23 के 280.44 लाख हेक्टेयर की तुलना में अधिक है। वहीं, उत्पादन बीते साल की तुलना में कम रहने का अनुमान है। तीसरे अग्रिम अनुमानों के तहत बागवानी फसलों का उत्पादन 3530.19 लाख टन होने का अनुमान है, जो बीते साल 2022-23 के 3550.48 लाख टन की तुलना में 22.94 लाख टन कम है।

सब्जियों की पैदावार अनुमान आंकड़े - 2023-24 के दौरान सब्जियों का उत्पादन लगभग 205.80 मिलियन टन होने की उम्मीद जताई गई है। टमाटर, पत्तागोभी, फूलगोभी, टैपिओका, लौकी, कद्दू, गाजर, ककड़ी, करेला, परवल और भिंडी के उत्पादन में इजाफा होगा। जबकि, आलू, प्याज, बैंगन, जिमीकंद, शिमला मिर्च तथा अन्य सब्जियों के उत्पादन में कमी की आशंका जताई गई है।

किन फलों की उपज बढ़ेगी और घटेगी

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के 2023-24 अंतिम अनुमान में फलों, शहद, फूलों, बागवानी फसलों, मसालों और सुगंधित एवं औषधीय पौधों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में फलों का उत्पादन बढ़ेगा। आम, केला, नींबू, अंगूर, कस्टर्ड सेब और अन्य फलों का उत्पादन 2022-23 की तुलना में 2.29 फीसदी बढ़कर यानी 112.73 मिलियन टन होने की उम्मीद है। वहीं सेब, मीठा संतरा, मैंडरिन, अमरूद, लीची, अनार, अनानास का उत्पादन 2022-23 की तुलना में घटने का अनुमान है।

टमाटर उपज 5 फीसदी बढ़ेगी

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान 2023-24 के अनुसार प्याज का उत्पादन 242.44 लाख टन होने की उम्मीद है। देश में आलू का उत्पादन 2023-24 में लगभग 570.49 लाख टन होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में उत्पादन में कमी दर्ज होना है। टमाटर का उत्पादन 2023-24 में 213.20 लाख टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल लगभग 204.25 लाख टन था यानी उत्पादन में 4.38 फीसदी का इजाफा होने की संभावना जताई गई है।

किसानों को सब्सिडी के साथ भरपूर मिलेगी यूरिया-डीएपी

खाते में डायरेक्ट आएगी खाद सब्सिडी! जिलों में लॉन्च होगा पायलट प्रोजेक्ट

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्र सरकार देश के कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डीबीटी के जरिये खाद सब्सिडी देने का काम शुरू कर सकती है। यहां डीबीटी का मतलब है कि जिस तरह पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है। ठीक उसी तरह किसानों को खाद सब्सिडी का पैसा खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा। इससे सब्सिडी के पैसे का सही-सही इस्तेमाल हो सकेगा और भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। इस पायलट प्रोजेक्ट को लेकर खाद इंडस्ट्री बहुत खुश है क्योंकि उसे लगता है कि नए साल में खाद और उर्वरक के क्षेत्र में बड़े सुधार हो सकते हैं। खबरों के मुताबिक खाद सब्सिडी के लिए सरकार एक मॉड्यूल पर काम कर रही है। हालांकि इसका काम कहां तक पहुंचा है, पायलट प्रोजेक्ट अभी किस दशा में है और कब तक पूरी प्लानिंग सार्वजनिक हो पाएगी, अभी कुछ पता नहीं है। सरकार की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। अभी इस पूरी प्लानिंग पर सरकार को खाद इंडस्ट्री के साथ चर्चा करनी है जिसके बारे में अधिकारी पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं।

डीबीटी से खाद सब्सिडी- खाद सब्सिडी की जहां तक बात है तो इसकी राशि 1,23,833.64 करोड़ तक पहुंच गई है जिसमें यूरिया की हिस्सेदारी 86,560 करोड़ और फॉस्फेटिक-पोटाश खाद की हिस्सेदारी 37,273.35 करोड़ है। यह राशि मौजदा वित्त वर्ष के अप्रैल-नवंबर अवधि के लिए है। अरबों रुपए के इस फंड का सही इस्तेमाल हो सके, इसके लिए सरकार डीबीटी जैसी भरोसेमंद स्कीम पर विचार कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इसे लेकर तैयारी भी शुरू हो चुकी है।

प्रोजेक्ट में सरकार को कई फायदे

अगर यह प्रोजेक्ट शुरू होता है तो इसमें सरकार को कई फायदे दिख रहे हैं। सबसे खास बात ये कि सरकार किसान के खेत और उसके रकबे के आधार पर सब्सिडी देगी। यहां तक कि किस फसल की बुवाई हुई है और खेत की मिट्टी कैसी है, इस आधार पर भी किसानों को खाद सब्सिडी का पैसा दिया जाएगा ताकि खाद और सब्सिडी का बेजा इस्तेमाल रोका जा सके। अभी भी पूरे देश में डीबीटी के जरिये खाद सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन इसका फायदा किसानों को नहीं देकर खाद कंपनियों को दिया जाता है। जिस कंपनी की खाद, खाद डीलरों के यहां पीओएस मशीनों के जरिये बिकती है। उसी आधार पर सरकार कंपनियों को सब्सिडी देती है। लेकिन अगर किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी का लाभ दिया जाए तो इसमें खर्च और लागत में बड़ी कमी आ सकती है।

खाद के साथ दूसरे प्रोडक्ट बेचने वाले जेल जाएंगे

रबी सीजन की फसलों की बुवाई की शुरुआत होते ही यूरिया और डीएपी खाद की मांग में इजाफा हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्हें सब्सिडी के साथ भरपूर खाद उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, कई राज्यों में खाद के बैग के साथ टैग कर दूसरे प्रोडक्ट खरीदने का दबाव किसानों पर बनाए जाने की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसा करने वाली सहकारी समितियों या निजी विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान सरकार ने तो ऐसा करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक्शन मोड में आ गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी किसानों को खाद की कमी होने देने और सस्ती कीमत में खाद देने के लिए एनबीएस सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। बीते माह कैबिनेट रबी फसल सत्र 2024-25 अक्टूबर से मार्च तक के लिए फॉस्फेटिक और पोटैसिक (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को स्वीकृति दे दी है।

मॉड्यूल को तैयार करेंगे

कृषि मंत्रालय ने अपनी डीबीटी की कई स्कीमों जैसे पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड और अभी हाल में शुरू हुई यूनीक आईडी स्कीम की डिटेल्स को खाद मंत्रालय के साथ शेयर किया है। इन स्कीम में किसानों की जमीन का विवरण, बोई जाने वाली फसल आदि की डिटेल्स होती हैं जिसके आधार पर किसानों को डीबीटी के जरिये खाद की सब्सिडी दी जा सकती हैं। इन सभी स्कीम की जानकारी को खाद मंत्रालय के साथ साझा किया गया है ताकि पायलट प्रोजेक्ट में मदद ली जा सके। खाद मंत्रालय इसी आधार पर सब्सिडी के मॉड्यूल को तैयार कर सकता है।

खाद मंत्रालय की जिम्मेदारी

कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि सब्सिडी का मॉड्यूल खाद मंत्रालय को तैयार करना है। इसमें वे तय करेंगे कि किन इलाकों में पहले यह डीबीटी स्कीम लॉन्च की जाएगी और शुरू में कितने किसानों को इसमें कवर किया जाना है। इसमें बटाईदार किसानों को भी शामिल किया जाएगा ताकि सरकार को पता चल सके कि सब्सिडी का पैसा कहां-कहां जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब्सिडी का पैसा केवल खेत के मालिक को ही मिले क्योंकि बड़ी संख्या में बटाईदार भी खेती करते हैं और उनका पैसा खर्च होता है।

अब यूरिया-डीएपी की कमी नहीं होगी

फॉस्फेटिक और पोटैसिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी मिलने से किसानों को रियायती, किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को यूरिया के एक बैग पर 2,100 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। जबकि, डीएपी खाद के एक बैग पर 1,083 रुपए की सब्सिडी किसानों को देने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री के अनुसार सरकार का प्रयास है कि किसानों को यूरिया और डीएपी की कोई कमी ना हो। राज्यों को उनकी मांग के अनुसार उर्वरकों का आवंटन कर दिया गया है।

किसानों के परिश्रम से बढ़ा सोयाबीन उत्पादन

मप्र में सोयाबीन खरीदी और भुगतान का बनेगा रिकॉर्ड

भोपाल। जागत गांव हमार

देश के कुल सोयाबीन उत्पादन का लगभग आधा उत्पादन मध्यप्रदेश में होता है। मध्यप्रदेश सम्पूर्ण देश में सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। किसानों के परिश्रम और किसानों के हित में शासन द्वारा की गई बेहतर व्यवस्थाओं से मध्यप्रदेश इस उपलब्धि को प्राप्त कर सका है। खरीफ की फसलों में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल सोयाबीन ही है। प्रदेश में सोयाबीन का रकबा और उत्पादन बढ़ रहा है। गत वर्ष की तुलना में प्रदेश के सोयाबीन के रकबे में 2 फीसदी वृद्धि हुई है। वर्तमान में प्रदेश का सोयाबीन का रकबा 66 लाख हेक्टयर से अधिक है। प्रदेश में 31 दिसंबर तक लगभग 6.5 से 7 लाख मीट्रिक टन तक सोयाबीन का उपार्जन होने का अनुमान है। गौरतलब है कि मप्र ने महाराष्ट्र और राजस्थान को पीछे छोड़कर सोयाबीन के सबसे बड़े उत्पादक राज्य बनने में सफलता प्राप्त की है। मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों को सोयाबीन के लिए 4 हजार 892 रुपए की राशि प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में देने की व्यवस्था की है। प्रदेश में उपार्जन की जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं।

भुगतान में टॉप 10 जिले

प्रदेश में दो लाख किसानों को 1957.1 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान उपार्जन के रूप में अब तक किया जा चुका है। प्रदेश में भुगतान का प्रतिशत 70.41 है। राशि के भुगतान में नीमच जिला अग्रणी है, जहां शत-प्रतिशत किसानों को राशि दी जा चुकी है। नीमच सहित विदिशा,राजगढ़, नर्मदापुरम, आगर मालवा, शहडोल, अनूपपुर, जबलपुर, उमरिया और खरगोन ऐसे दस शीर्ष जिलों में शामिल हैं, जहां 75 प्रतिशत किसानों को राशि का भुगतान किया जा चुका है।

सोयाबीन परिवहन का काम 95 फीसदी पूरा

सोयाबीन के परिवहन का कार्य भी प्रदेश में 95 प्रतिशत हो चुका है। प्रदेश में मालवा अंचल में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन होता है। किसानों के पंजीयन से लेकर, आवश्यक बारदाने की व्यवस्था, परिवहन,भंडारण और राशि के भुगतान के कार्यों की राजधानी से लेकर जिलों तक नियमित समीक्षा भी की जा रही है।

बिना कठिनाई के हो भुगतान

किसानों से उपार्जित सोयाबीन के लिए राशि का भुगतान बिना कठिनाई के किया जा रहा है। सोयाबीन के भंडारण और उपार्जित सोयाबीन की सुरक्षा के प्रबंध भी किए गए हैं। किसानों को उपार्जन की आधुनिक व्यवस्थाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। मप्र में पहली बार सोयाबीन का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जा रहा है। ई-उपार्जन पोर्टल का उपयोग भी किया जा रहा है। किसानों को ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था है। **-डॉ. मोहन यादव, सीएम**

देश में 90 हजार से ज्यादा बायोगैस प्लांट स्थापित किए

देश के किसानों का हर महीने एक हजार रुपए बचा रही सिस्टमा बायो

भोपाल। जागत गांव हमार

बायोगैस के जरिए किसानों और ग्रामीणों के खर्च को कम करने में मदद कर रही सिस्टमा बायो ने कहा है कि वह किसानों के हर महीने 1 हजार रुपए से ज्यादा का खर्च बचा रही है। कंपनी के अनुसार देशभर में उसने किसानों और ग्रामीणों के यहां 90 हजार से ज्यादा बायोगैस प्लांट स्थापित किए हैं। इन प्लांट से मिलने वाले ईंधन के इस्तेमाल से कुकिंग गैस एलपीजी पर होने वाले खर्च को बचाया जा रहा है। इसके साथ ही कंपनी पर्यावरण को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सिस्टमा बायो के साउथ एशिया डायरेक्टर अतुल मित्तल ने एक विशेष बातचीत में प्लांट लगाने का तरीका और इस पर आने खर्च समेत कई बिंदुओं पर खुलकर बात रखी। सिस्टमा बायो में डायरेक्टर फॉर साउथ एशिया अतुल मित्तल ने बताया कि बायोगैस एक जैविक ईंधन है, जो कार्बनिक पदार्थों के विघटन से बनता है। इस विघटन को एनारोबिक डाइजेशन बोलते हैं। ये विघटन किसी भी जैविक पदार्थ का हो सकता है, जैसे गाय या भैंस का गोबर हो, पोल्ट्री का गोबर हो या स्वाइन फार्मिंग का गोबर हो। उनके प्राकृतिक विघटन से जो पदार्थ बनता है उसे बायोगैस कहते हैं। बायोगैस में मीथेन गैस होती है, जिसको कुकिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा क्लीन एनर्जी और जैविक खाद बनाई जा रही है।

किसान हर महीने 1000 रुपए तक का खर्च बचा रहे

अतुल मित्तल ने कहा कि बायोगैस प्लांट से पैदा होने वाली बायोगैस से कुकिंग गैस बनती है। जिन किसानों के यहां प्लांट लगाए गए हैं वो उस गैस से खाना बनाते हैं और उन्हें एलपीजी सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती है। उन परिवारों को चूल्हे के लिए लकड़ी, कोयला भी नहीं जुटानी पड़ती। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की उज्ज्वला स्कीम बहुत अच्छी है लेकिन, रीफिलिंग में काफी दिक्कत आती है। किसान बार-बार सिलेंडर नहीं खरीदता है। ऐसे में बायोगैस प्लांट लगाने के बाद उसका गैस सिलेंडर का खर्च बच जाता है। लकड़ी और कोयले की भी बचत होती है। अनुमान है कि किसी भी साधारण परिवार 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रतिमाह जो कुकिंग गैस के जरिए बचा सकता है।

बायोगैस प्लांट लगाने की आसान प्रक्रिया

अतुल मित्तल ने बताया कि बायोगैस प्लांट्स लगाने की प्रक्रिया बहुत आसान है। हमारी टीम किसानों के घर जाती है और उनको सिस्टम बायो के लेटेस्ट बायोगैस के बारे में जानकारी देती है और उन्हें ट्रेनिंग देती है। बायोगैस प्लांट लगाने के लिए एक छोटा सा करीब 1.5 फीट या 2.5 फीट का गड्ढा 2.5 मीटर के आकार का खोदना होता है। हमारे टेक्नीशियन्स प्लांट को उस गड्ढे में इनस्टॉल करते हैं। उन्होंने कहा कि की शुरुआत में 500 किलो गोबर रोज डालना होता है। इसके 30-35 दिन बाद गैस निकलना शुरू हो जाती है, जो रोजाना निकलती है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम प्लांट मालिक को कुकिंग गैस जलाने से लेकर उसके इस्तेमाल का तरीका भी बताते हैं।

किसान के लिए 10 हजार रुपए प्लांट लगाने का खर्चा

उन्होंने कहा कि देशभर में हमने 90 हजार बायोगैस प्लांट लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि छोटे और सीमांत किसानों के यहां प्लांट लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि दो घन मीटर का बॉयोगैस प्लांट लगाने में आने वाला सारा खर्च 35-36 हजार के आसपास होता है। उन्होंने कहा कि किसानों पर इस रकम को बोझ नहीं बनने देने के लिए हम कार्बन क्रेडिट के जरिए उनकी मदद करते हैं। इससे किसान पर बायोगैस प्लांट लगाने का खर्च घटकर करीब 10 हजार के आसपास आ जाता है।

कई राज्यों के साथ साझेदारी

आने वाले समय में प्लांट की संख्या में तेज बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। प्लांट लगाने का विस्तार डेयरी संचालकों, पशुपालकों, गौशालाओं समेत कृषि से जुड़े संस्थानों में करने की योजना है। बायोगैस प्लांट लगाने के लिए हम करीब 22 राज्यों में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गुजरात सरकार के साथ काफी अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट्स पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भी काम शुरू हो चुका है और बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा तेलंगाना सरकार के हम कोऑपरेटिव डेयरी या फिर प्राइवेट संस्थानों के साथ भी काम कर रहे हैं।

अपनी मृदा का स्वास्थ्य जानें, मृदा परीक्षण क्यों है जरूरी

» डॉ. दीपक कुमार
» डॉ. शिवा तिवारी
» डॉ. सुनील शुक्ला
» डॉ. अल्का सुमन
- मृदा एवं जल संरक्षण अभियांत्रिकी विभाग, गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय पंतनगर, उत्तराखंड

मृदा परीक्षण से हमें मृदा की गुणवत्ता, पोषक तत्वों की मात्रा आदि की जानकारी प्राप्त होती है, जिसके कई फायदे हैं जैसे मृदा में कौन-कौन से पोषक तत्व कम हैं, यह जानने से किसानों को सही उर्वरकों का चयन करने में मदद मिलती है, जिससे फसलों की उपज और गुणवता में वृद्धि होती हैं, जरूरत से अधिक उर्वरक डालने से ना केवल खर्च बढ़ता है, बल्कि मृदा की उर्वरता भी खराब होती है। सही पोषक तत्वों का चयन करके अपने खर्च को कम कर सकते हैं। ज्यादा उर्वरक और रसायनो का इस्तेमाल पर्यावरण और जल स्त्रोतों को प्रदूषित करता है।

समय-समय पर मृदा की जांच करके उसकी उर्वरक क्षमता को बनाए रख सकते हैं, जिससे भूमि लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहती है। आज के समय में सटीक खेती का महत्व बढ़ा रहा है जिसमें मृदा परीक्षण की अहम भूमिका है।

मृदा नमूना एकत्रीकरण विधि: मृदा परीक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि मृदा का सही नमूना एकत्र करना। खेत में अलग- अलग स्थानों से नमूनों का एकत्रित करें। या खेत में ज़िग जैग चलते हुए नमूनों को एकत्रित करें। एकत्रित की गई पूरी मृदा को हाथ से अच्छी तरह से मिला ले तथा साफकपड़े पर डालकर गोल ढेर बना लें। अंगुली से ढेर को चार बराबर भागों में बाट दें, जिसमें से सामने के भाग हटा दें एवं शेष दो भागों की मृदा पुन: अच्छी तरह से मिला लें व गोल ढेर बनायें। यह प्रक्रिया तब तक दोहरायें जब तक लगभग आधा कि.ग्रा. मृदा शेष रह जाये । मृदा नमूने को सुखाकर साफप्लास्टिक थैली में रखें तथा साथ में एक सूचना पत्रक जिस पर समस्त जानकारी लिखी हो थैली में साथ रख दें ।

गड्ढा खोदने की विधि: जिस क्षेत्र से नमूना लेना है उसमें 10-15 स्थानों पर निशान बना लें, ताकि क्षेत्र के सभी हिस्से शामिल हो सकें, चुने गये स्थानों पर ऊपरी सतह से घास-फूस कूड़ा करकट आदि हटा दें। इन सभी स्थानों पर 'ऑगर होल', खुरपी या फावड़ा की मदद से 'वी' कार का गड्ढा खोदें। सामान्यत: खेत में सीजनल पासल एवं नर्सरी में 0-15 से.मी. गहराई का गड्ढा खोदें एवं वानिकी प्रजातियों के लिए 0-30 से.मी. एवं 30-60 से.मी. गहराई का गड्ढा खोदें। गड्ढे को एक तरफसाफकरके खुरपी से ऊपर से नीचे तक 2 से.मी. मोटी मृदा की सतह को निकाल लें तथा साफ बाल्टी या ट्रे में रखें।

मृदा परीक्षण की शुरुआत: भारत में मृदा परीक्षण कार्यक्रम वषर्ज 1955-56 के दौरान भारत सरकार के तहत 16 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के साथ शुरू किया गया। जिसका उद्देश्य मृदा की उवज़रता और उर्वरक निर्धारण के लिए था। वर्तमान में देश में 7949 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ है, जिनमें 1239 स्थिर प्रयोगशालाएँ, 165 चलित प्रयोगशालाएँ 6337 लघु प्रयोगशालाएँ और 154 ग्राम स्तरीय प्रयोगशालाएं शामिल हैं। मध्यप्रदेश में 727 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ है जिनमें 91 स्थिर,10 मोबाइल और 626 लघु प्रयोगशालाएँ शामिल हैं।

मृदा परीक्षण केन्द्र: किसान अपने मृदा नमूने को परीक्षण के लिए राज्य स्तरीय सरकार के कृषि विभाग (ब्लाक, तहसील और जिला स्तर), कृषि विज्ञान केन्द्र (जिला स्तर), कृषि मण्डी, आई सी ए आर संस्थान (भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल), अनुसंधान विश्वविद्यालय, जबलपुर), गैर-लाभकारी संगठन और निजी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ से परीक्षण करा सकते हैं। इनमें से कुछ संस्थाएँ नि:शुल्क परीक्षण करती है तथा कुछ संस्थाएँ परीक्षण शुल्क लेती है।

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जलबपुर की सवर्धन शाखा के अंतर्गत चलित मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में मृदा नमूनों का परीक्षण शुल्क

क्रमांक	मृदा परीक्षण विवरण	प्रस्तावित परीक्षण शुल्क (प्रति नमूना)
भौतिक परीक्षण:		
1	थोक घनत्व	30.00
2	विशिष्ट गुरुत्व	30.00
3	सरंध्रता	30.00
4	जल धारण क्षमता	30.00
5	आर्द्रता	30.00
	मृदा संरचन	40.00
रासायनिक परीक्षण:		
1	पी. एच	40.00
2	ई. सी.	40.00
3	काबजनिक तत्व	60.00
4	नाइट्रोजन	80.00
5	फॉस्फोरस	80.00
6	पोटेशियम	80.00
7	कैल्सियम	60.00
8	सोडियम	60.00
सूक्ष्म पोषक तत्वों का परीक्षण:		
1	जिंक	150.00
2	कापर	150.00
3	आयरन	150.00
4	मैंगनीज	150.00

योजनाओं की कमियां: भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 328.7 मिलियन हेक्टेयर है। भारत की कृषि योग्य भूमि 180.11 मिलियन हेक्टेयर है, कुल बोया गया क्षेत्र 141 मिलियन हेक्टेयर है । भारत सरकार की मृदा परीक्षण के लिए जानी जाने वाली सबसे बड़ी योजना मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, जिसमें वर्ष 2022-2023 में 38,02,893 नमूने एकत्रित किये जिसमे से 36,11,236 नमूना का परीक्षण किया गया,फिर 42,22,363 मृदा स्वास्थ्य काडज़ किसानों को भेजे गये, जो यह दर्शाता है कि केवल कुछ किसानों को ही इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। मृदा नमूनों की संख्या कम व कार्ड की संख्या अधिक होना ये दर्शाती है कि प्रत्येक किसान के खेत का अलग- अलग मृदा परीक्षण नहीं किया गया है। इस योजना का उद्देश्य यह भी है कि उर्वरकों का जरूरत से अधिक उपयोग ना किया जाए परंतु प्रत्येक वर्ष उर्वरकों का उत्पादन व उपभोग बढ़ता जा रहा है।

किसानों की भूमिका: मृदा परीक्षण के सफ्ल बनाने के लिए किसानों के एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि प्रत्येक किसान यदि अपने मृदा नमूने को परीक्षण केन्द्र तक परीक्षण के लिए लेकर जाये फिर उसके परीक्षण की रिपोटज़ प्राप्त करने जाये तो अतिरिक्त शुल्क व अतिरिक्त समय लगेगा। यदि सभी किसान एक दिन तय करें जिसमें सभी किसानों के नमूनों को एक साथ परीक्षण केन्द्र तक पहुंचाया जाए इसमें वह अपने गांव के ग्रामीण विकास अधिकारी की सहायता लें जिससे यह काम और आसानी से हो सके इस तरह किसानों के साथ मिल-जुलकर काम करने से अतिरिक्त खर्च व समय को बचाया जा सकता है।

बकरियों में होने वाले संक्रामक रोग, बचाव और सुरक्षा

» डॉ. योगिता पांडेय
» डॉ. अखिलेश पांडेय
» डॉ. सुनील शुक्ला
» डॉ. अल्का सुमन
- असिस्टेंट प्रोफेसर, वेटरनरी एनाटोमी, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय मह
- एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रभारी, अनुवांशिकी विभाग, प. चि. एवं प. पा. महाविद्यालय मह
- एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रभारी, वेटरनरी एनाटोमी, प.चि.एवं प. पा. महाविद्यालय मह, इंदौर
- असिस्टेंट प्रोफेसर, वेटरनरी एनाटोमी, प.चि.एवं प. पा. महाविद्यालय मह, इंदौर

बीमारी के कारण होने वाली समस्या का इलाज करने या उस पर प्रतिक्रिया करने की तुलना में बीमारी को रोकना आसान है। रोग नियंत्रण या सुरक्षा रोग निवारण के सबसे प्रभावी साधनों में से एक है, कुछ रोग बैक्टीरिया के कारण होते हैं जैसे कि केसियस लिम्फैडेनाइटिस का कारण बनते हैं। कुछ वायरस द्वारा, जैसे कि कैप्रिन आर्थराइटिस एन्सेफ्लाइटिस या कोवसीडिया जैसे परजीवियों द्वारा।

बकरियों में रोग का प्रसार बहुघटकीय है। यह प्रबंधन कारकों (स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा स्थिति, आदि), पर्यावरणीय कारकों (तापमान, भंडारण दर, चारागाह की स्थिति, आदि), और रोग एजेंट पर निर्भर करता है।

बकरी के झुंड में बीमारियों के प्रसार या संचरण की संभावना निम्न कारकों से होती है।

रोगग्रस्त बकरियों या रोग पैदा करने वाली स्वस्थ बकरियों / वाहक पशु द्वारा।

वाहनों, उपकरणों, कपड़ों और अन्य दूषित निर्जीव वस्तुओं से मृत पशुओं के शवों का उचित एवं समय पर निपटान न होने से दूषित खाद्य पदार्थों और पानी से खाद का उचित रख-रखाव न होने से।

गैर-पशुधन वाहक (पक्षी, कृंतक, कीड़े, बिल्लियाँ, आदि) से रोग संचरण के सभी संभावित मार्गों के कारण एक प्रभावी सुरक्षा समाधान जटिल हो जाता है एक प्रभावी रोग नियंत्रण के निम्न बिंदु हैं।

अवांछित यातायात पर नियंत्रण, स्वच्छता का ध्यान रखना, प्रबंधन करने वाले की व्यक्तिगत स्वच्छता। बकरियों के पुरे झुंड का स्वास्थ्य, संक्रमित या नए जानवरों को अलग रखना। वैक्सीन एवं प्रबन्धन के अच्छे रिकॉर्ड रखें।

खाद्य सामग्री एवं पानी की स्वच्छता एवं सुरक्षा का ध्यान रखें, खाद संदूषण को रोकने का प्रयास करें।

भोजन उपकरण को नियमित रूप से साफऔर कीटाणुरहित करें, जो क्लोरीन, आयोडीन, या क्वाटेनरी अमोनिया उत्पादों (क्यूएपी) के साथ किया जा सकता है।

जानवरों को दवा देने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों, विशेष रूप से कई जानवरों पर उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को नियमित रूप से साफ और कीटाणुरहित करें।

बीमार पशुओं के उपचार के लिए निवास क्षेत्र रखें। बकरियों के बीमार होने या अप्रत्याशित रूप से मरने पर पशुचिकित्सक से परामर्श लें। दूषित वाहनों और उपकरणों को साफकरें।

उन झुंडों का स्वास्थ्य इतिहास जानें जहां नए जानवर खरीदे जाते हैं। पशुओं को साफवाहनों में ले जाएँ, झुंड में लाए गए नए जानवरों की स्वास्थ्य स्थिति जानें और नए और बीमार जानवरों को अलग रखें। समय अनुसार टीकाकरण का ध्यान रखें।

जो उत्पादक अपने खेत में बीमारी के आगमन और प्रसार को सफलतापूर्वक नियंत्रित करते हैं, वे न केवल खुद को बल्कि पूरे उद्योग को भी लाभान्वित करते हैं। रोग नियंत्रण से दवा और उपचार की लागत कम हो जाती है और उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पादों की सुरक्षा और संपूर्णता के संबंध में उपभोक्ता का विश्वास बढ़ता है। बीमारी की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करने वाले प्रबंधन प्रथाओं को ट्रैक और मान्य करना, पर्यावरण को स्वच्छ रखना, बीमार और स्वस्थ जानवरों के बीच क्रॉस-संदूषण को रोकना और नियमित मूल्यांकन शामिल करना चाहिए जो प्रभावी ढंग से प्रसार को नियंत्रित करता है।

स्वस्थ बकरियां	बीमारी के लक्षण
अच्छी भूख	अपर्याप्त भूख
चमकदार कोट	फीका कोट, बाल झड़ रहे हैं
मिलनसार	एकांत
चमकदार और साफ आँखें	बहती आँखें
अच्छी तरह मांसल	वजन घटना
शरीर का सामान्य तापमान 103.1°– 104.9°F	बुखार 105.8°F या इससे अधिक, 98°F से नीचे हाइपोथर्मिया
मजबूत टांगें और पैर	लंगड़ापन, जोड़ों में सूजन
गुलाबी मसूड़े	एनीमिया (पीले मसूड़े)
दृढ़ गोलीयुक्त	दस्त
शरीर के किसी भी अंग में सूजन नही	शरीर के किसी अंग में सूजन
जुगाली करना	जुगाली नहीं कर रहा

जलवायु परिवर्तन से ठंडे खून वाले जीवों में बढ़ रहे हैं घातक संक्रमण

दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में भारी वृद्धि हो रही है और इससे संक्रामक रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है, जिससे प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। तापमान में वृद्धि और संक्रमण मिलकर जीवों के स्वास्थ्य को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, यह स्पष्ट नहीं है। ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय (यूबीसी) के एक नए अध्ययन से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कोरल, कीड़े और मछली जैसे ठंडे खून वाले जीवों के लिए जीवाणु और फंगल संक्रमण घातक हो सकते हैं। जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को नुकसान पहुंच सकता है, इसकी वजह से लोगों पर बढ़ते तापमान का और क्या असर पड़ सकता है इस पर कई सवाल उठते हैं।

गर्म होती दुनिया में ठंडे खून वाले जीवों पर असर: शोधकर्ताओं ने बैक्टीरिया, फंगल और अन्य संक्रमणों से पीड़ित ठंडे खून वाले जानवरों पर 60 प्रयोगात्मक अध्ययन किए, जिसमें पाया गया कि ठंडे खून वाले जानवर सीधे तापमान पर निर्भर होते हैं और इसलिए, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हो सकते हैं। अध्ययनों में जमीनी कीटों, मछलियों, मोलस्क और कोरल सहित 50 प्रजातियों को शामिल किया गया जो ग्रह पर सबसे अधिक जैव विविधता वाले और सबसे अधिक खतरे वाले पारिस्थितिकी तंत्रों में से कुछ हैं। शोधकर्ताओं ने साख्यिकीय मॉडलों का उपयोग करते हुए पाया कि जीवाणु संक्रमण से ग्रस्त ठंडे खून वाले जीवों के सामान्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की तुलना में अधिक तापमान के संपर्क में आने पर उनके मरने की अधिक आशंका होती है।

फंगल संक्रमण और ठंडे खून वाले जीव: शोध में विश्लेषण से पता चला कि फंगल रोगजनकों से संक्रमित जीवों ने एक विशिष्ट तापमान सीमा के भीतर गर्मी के प्रभाव को महसूस किया। तापमान बढ़ने पर वे अधिक बार नहीं मरे, जब तक कि तापमान कवक की आदर्श सीमा की ओर नहीं बढ़ा, जिसे थर्मल ऑप्टिमम के रूप में जाना जाता है। इस बिंदु पर, संक्रमित जानवरों के मरने की अधिक आशंका जताई गई थी। हालांकि जब तापमान इतना ज्यादा हो गया कि कवक जीवित नहीं रह सके, तो संक्रमित जानवरों में मृत्यु दर कम हो गई।

इसका क्या मतलब है?: इन निष्कर्षों से पता चलता है कि बढ़ती गर्मी से ठंडे खून वाले जानवरों के लिए अधिक खतरा हो सकता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह शोध पीएलओएस बायोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया है।

एग्री मार्केटिंग पॉलिसी का तैयार किया था ड्राफ्ट

किसानों के विरोध के बीच आईएएस किदवई को केंद्र ने हटाया

भोपाल।

केंद्र सरकार की नई एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी ड्राफ्ट के खिलाफ किसान संगठनों के भारी आक्रोश के बीच केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस फैज अहमद किदवई का केंद्रीय कृषि मंत्रालय से तबादला कर दिया है। किदवई को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) का प्रमुख नियुक्त किया है। किदवई की लीडरशिप में ही 15 सदस्यीय टीम ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग की राष्ट्रीय नीति का ड्राफ्ट तैयार किया था। इस पॉलिसी पर सार्वजनिक सुझाव लिया जा रहा था। लेकिन किसान संगठनों ने इसका यह कहकर विरोध करना शुरू कर दिया था कि इस पॉलिसी में किसानों के हितों की बलि चढ़ाने और कारपोरेट को मुनाफा दिलाने की साजिश है। आरोप यह लगाया जा रहा है कि इस पॉलिसी के जरिए बैक डोर से तीन कृषि कानूनों को लागू किया जा रहा है। बहरहाल, अब देखना यह है किदवई के ट्रांसफर के बाद केंद्र सरकार की नई एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी का क्या होगा।

पॉलिसी तैयार करने में भूमिका

इस पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने में किदवई की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। केंद्र सरकार ने किदवई के नेतृत्व में पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 25 जून 2024 को ऑर्डर निकाला था। किदवई के नेतृत्व वाली कमेटी द्वारा तैयार किए गए मसौदे में सभी राज्यों में प्राइवेट मंडी बनाने की बात कही गई है। किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ किसान संगठनों का कहना है कि निजी मंडी बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से नीचे फसलों की खरीद न करने की शर्त भी होनी चाहिए। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर करीब सवा तीन सौ दिन से एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने भी नई एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी के मसौदे का विरोध किया है।

शुभा ठाकुर का भी तबादला

मध्य प्रदेश कैडर के 1996 बैच के आईएएस अधिकारी किदवई कमल नाथ के सीएम रहते उनके सचिव भी रह चुके हैं। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के रहने वाले हैं। बहरहाल, डीजीसीए में महानिदेशक के तौर पर उनका रैंक एवं वेतनमान भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के समान होगा। इसके अलावा, 1989 बैच की सीएसएस शुभा ठाकुर को अब गृह मंत्रालय के अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी तक वो कृषि मंत्रालय में एडिशनल सिक्रेटरी के पद पर कार्यरत थीं। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अशुतोष अग्निहोत्री को भारतीय खाद्य निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में खरीद दिसंबर में शुरू होगी

मप्र में 2.48 मीट्रिक टन धान किसानों से खरीदी पिछले साल से अधिक एमएसपी पर धान खरीदी

भोपाल। जागत गांव हमार

देश में इस साल एमएसपी पर धान की खरीद के आंकड़े में बढ़ोतरी हुई है। पंजाब में भंडारण की कमी के कारण धान खरीद की सुस्त शुरुआत के बावजूद, इस सीजन (2024-25) में सरकार का धान खरीद अभियान 48.3 मिलियन टन (एमटी) को पार कर गया है, जो पिछले साल की तुलना में थोड़ी अधिक है। अधिकारियों ने बताया कि चालू सीजन (अक्टूबर-सितंबर) के लिए धान खरीद के कामों में पिछले छह सप्ताह में तेजी आई है, क्योंकि सरकार ने पंजाब से जरूरत से ज्यादा चावल स्टॉक को निकाल लिया है, जो केंद्रीय पूल अनाज स्टॉक में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। अब तक भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की एजेंसियों ने एमएसपी पर 48.3 मीट्रिक टन धान की खरीद की है, जिनमें से अधिकतर पंजाब में (17.35 मीट्रिक टन), छत्तीसगढ़ (8.89 मीट्रिक टन), हरियाणा (5.37 मीट्रिक टन), तेलंगाना (4.26 मीट्रिक टन), उत्तर प्रदेश (3.86 मीट्रिक टन), मध्य प्रदेश (2.48 मीट्रिक टन और ओडिशा (1.28 मीट्रिक टन) के किसानों से खरीदा गया है।

49 मीट्रिक टन चावल खरीदने का लक्ष्य- एजेंसियां चालू खरीफ सीजन में प्रमुख अनाज जरूरत से ज्यादा राज्यों से 49.21 मीट्रिक टन चावल (73.27 मीट्रिक टन धान) खरीदने का लक्ष्य बना रही हैं, जबकि 2023-24 में किसानों से 52.4 मीट्रिक टन (78.16 मीट्रिक टन धान) खरीदा गया था।

पंजाब और हरियाणा धान की खरीद हुई पूरी

1 अक्टूबर से शुरू हुई खरीद की शुरुआत में पंजाब और हरियाणा में भंडारण की जगह की कमी के कारण खरीद धीमी रही। अधिकारियों ने बताया कि पंजाब और हरियाणा में एजेंसियों द्वारा खरीद पूरी हो चुकी है, जबकि अन्य राज्यों के किसान अभी भी अपनी उपज ला रहे हैं और मार्च, 2025 तक खरीद जारी रहने की उम्मीद है।

इन राज्यों में पिछले साल से अधिक खरीद

केंद्र द्वारा चरणबद्ध तरीके से पंजाब से जरूरत से ज्यादा धान की निकासी के साथ, पिछले महीने खरीद में तेजी आई है और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी पर अधिक खरीद की सूचना दी है। पंजाब, जिसने केन्द्रीय पूल अनाज स्टॉक में सर्वाधिक 17.35 मीट्रिक टन धान का योगदान किया था। उसमें एजेंसियों द्वारा खरीद गई एक वर्ष पूर्व की तुलना में 6 फीसदी कम है।

पूर्वी-दक्षिणी राज्यों में दिसंबर में होगी खरीद

कृषि मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि फसल वर्ष 2024-25 (जुलाई-जून) में खरीफ चावल उत्पादन रिकॉर्ड 119.93 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा, जबकि फसल वर्ष 2023-24 में यह 113.26 मीट्रिक टन होगा। एफसीआई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को आपूर्ति के लिए सालाना 38 मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति करता है। बता दें कि केंद्रीय पूल चावल स्टॉक में मुख्य योगदानकर्ता पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हैं। इस मौसम में कुल चावल खरीद का लगभग 80 फीसदी खरीफ सीजन में होता है। वहीं, पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में खरीद दिसंबर में शुरू होगी।

मक्का समर्थन से 10 फीसद महंगा बिके तो मिले इंपोर्ट की अनुमति

भोपाल। जागत गांव हमार

मक्का का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। खासतौर पर पोल्ट्री सेक्टर में मक्का को लेकर हलचल लगातार बढ़ रही है। पोल्ट्री से जुड़े लगभग सभी कार्यक्रम में मक्का का मामला उठाया जा रहा है। हाल ही में पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया समेत दूसरी एसोसिएशन के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल पशुपालन और डेयरी सेक्रेटरी से मिला। पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल होने वाली मक्का और सोयामील पर चर्चा हुई। पोल्ट्री की मौजूद सबसे बड़ी परेशानी से अवगत कराया। वहीं इस परेशानी को दूर करने के लिए कुछ मांगें भी अधिकारियों के सामने रखीं। इसमे सबसे प्रमुख मांग मक्की की कमी और उसके बढ़ते रेट को लेकर रखी गई। पीएफआई ने मांग करते हुए कहा है कि जब बाजार में मक्का का रेट न्यूनत्तम समर्थन मूल्य से 10 फीसद ज्यादा हो तो मक्का इंपोर्ट करने की अनुमति दी जाए। इसके साथ मक्का और सोयामील की क्वालिटी को लेकर भी कुछ मांग डेयरी सेक्रेटरी के सामने रखी गईं।

महंगे हो रहे अंडा-चिकन - पीएफआई के प्रेसिडेंट रनपाल डाहंडा ने पशुपालन और डेयरी सेक्रेटरी अलका उपाध्याय समेत सभी अफसरों को अंडे और चिकन के बढ़ते रेट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे लगातार अंडे-चिकन की लागत बढ़ रही है। उनका कहना है कि पोल्ट्री फीड लगातार महंगा होता जा रहा है। जिसकी वजह से मजबूरी में अंडा-चिकन के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। अगर पोल्ट्री फार्मर को बचाना है और अंडे-चिकन की महंगाई को कम करना है तो जीएम मक्का इंपोर्ट करने की अनुमति मिलनी चाहिए। साथ ही अगर बाजार में मक्का का दाम एमएसपी से 10 फीसद ज्यादा होता है तो तुरंत ही मक्का इंपोर्ट करने की अनुमति मिले।

सोयामील की सुधरे क्वालिटी

रनपाल डाहंडा ने मांग करते हुए कहा कि मक्का डीडीजीएस के लिए बीआईएस मानक बनाए जाएं, क्योंकि इसमें एफ्लाटॉक्सिन की क्वालिटी संबंधी समस्याएं आ रही हैं। इसी तरह सोयामील में मिलावट का मुद्दा भी बड़ा है। जिसका सीधा असर पोल्ट्री प्रोडक्ट पर पड़ता है। इसलिए सोयामील के लिए भी सख्त बीआईएस मानक लागू किए जाने चाहिए। इस मौके पर ज्वाइंट सेक्रेटरी वषा जोशी, एनीमल हसबेंडरी कमिश्नर अभिजीत मित्रा, पीएफआई के वाइस प्रेसिडेंट संजीव गुप्ता, सेक्रेटरी रविन्द्र सांधू, ज्वाइंट सेक्रेटरी रिकी थापर समेत तमाम लोग मौजूद थे।

जनवरी से दिसंबर, किस महीने में कौन सी सब्जी की खेती करें किसान

भोपाल। जागत गांव हमार

किसान कौन से महीने में कौन सी सब्जी की खेती करें, इसे लेकर लोगों में असमंजस बना रहता है। वहीं किचन गार्डन में कब कौन सी सब्जी लगाएं, कृषि वैज्ञानिकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उपयुक्त समय पर फसल लगाने से उत्पादन बेहतर होता है। किस महीने में किस सब्जी की खेती करें ....।

जनवरी: बैंगन, मिर्च, गाजर, मूली, पालक, टमाटर, शलगम जैसी फसलें उगाने के लिए उपयुक्त समय है।

फरवरी: मूली, गाजर, पालक, धनिया, टमाटर, बीन्स और लौकी जैसी सब्जियों के लिए अच्छा महीना है।

मार्च: गर्मियों की सब्जियां जैसे लौकी, तोरई, तरबूज, ककड़ी और करेला उगाने के लिए सही समय है।

अप्रैल: लौकी, ककड़ी, करेला, तोरई, तरबूज, टिंडा आदि की बुवाई उपयुक्त है।

मई: ग्रीष्मकालीन सब्जियों जैसे लौकी, ककड़ी, करेला, तोरई और टिंडा का उत्पादन हो सकता है।

जून: भिंडी, लौकी, करेला, तोरई, तरबूज जैसी सब्जियों के लिए सही समय है।

जुलाई: भिंडी, तोरई, लौकी, तरबूज, खीरा, करेला, पालक आदि की बुवाई के लिए उपयुक्त है।

अगस्त: पालक, मूली, गाजर, मेथी, धनिया और चौलाई जैसी फसलें लगाई जा सकती हैं।

सितंबर: आलू, टमाटर, गोभी, मटर, मूली, गाजर, धनिया जैसी फसलें इस माह लगाई जा सकती हैं।

अक्टूबर: गोभी, मूली, गाजर, पालक, धनिया और ब्रोकली उगाने के लिए सही समय है।

नवंबर: मटर, गोभी, गाजर, धनिया, ब्रोकली और पालक जैसी फसलें लगाई जा सकती हैं।

दिसंबर: टमाटर, बैंगन, गोभी, गाजर, पालक, मटर जैसी फसलें इस महीने उगाई जा सकती हैं।

अगर सब्जियों को तय समय पर बोया जाए तो उत्पादन बेहतर होता है और आप मौसम सब्जी का मजा ले सकेंगे।

लाभ: इस चक्र से किसान यह जान सकते हैं कि किस महीने में कौन-सी फसल उपयुक्त है यह जानकारी मौसम के अनुसार खेती की योजना बनाने में मदद करती है। उपयुक्त समय पर फसल लगाने से उत्पादन बेहतर होता है।

प्रदेश में 1 जनवरी से यह व्यवस्था लागू

तेज भुगतान और उपज तौल के लिए 41 मंडियां डिजिटल हुईं, किसानों को फायदा

भोपाल। जागत गांव हमार

अनाज मंडियों में किसानों को होने वाली तौल और भुगतान संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए मंडियों को डिजिटल किया जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की 41 बी क्लास मंडियों को डिजिटल कर दिया गया है। इन मंडियों को नए साल 2025 की पहली तारीख से ई-मंडी योजना के साथ जोड़ दिया गया है। ई-मंडी मोबाइल ऐप से किसानों को यह पता चल सकेगा कि उनकी उपज किस व्यापारी ने कितने दाम पर खरीदी है। सरकार के इस फैसले से राज्य के 81 लाख से अधिक किसानों को फायदा पहुंचने वाला है।

मंडियों में किसानों को अपनी उपज बिक्री के लिए कई कई दिन तक तौल कराने के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। ऐसे में बारिश या विपरीत मौसम से उनकी उपज को नुकसान पहुंचता है। धान, गेहूं, गन्ना समेत अन्य फसलों के मामले में विपरीत मौसम के चलते किसानों को आथिज्क नुकसान के कई मामले भी सामने आ चुके हैं। बीते दिनों हुई बारिश से मंदसौर मंडी में रखा कई हजार क्विंटल लहसुन भी गया और पानी बहता देखा, जिसे किसान बोरियों में बटोरते देखे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मंडियों बारिश या विपरीत मौसम से उपज को बचाने के लिए पर्यात उपाय करने के निर्देश जारी करने पड़े।

किसानों की उपज खरीद के लिए तेज तौल प्रक्रिया और भुगतान करने के लिए मंडियों को डिजिटल किया जा रहा है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को नुकसान से बचाया जा सकेगा। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्य की 41 बी क्लास मंडियों को डिजिटल कर दिया गया है। 1 जनवरी से यह व्यवस्था लागू कर दी गई है।

41 मंडियां डिजिटल हुईं

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मंडी बोर्ड) के अनुसार ई-मंडी योजना से किसानों को त्वरित समाधान मिलेगा। अब मध्य प्रदेश की इन 41 बी क्लास कृषि उपज मंडियों में ई-मंडी योजना के तहत नीलामी हो सकेगी। इसके अलावा उपज की तौल और किसानों को रकम भुगतान की प्रक्रिया भी पूरी तरह डिजिटल हो गई है। राज्य में पहले से 42 उपज मंडियां ई-मंडी योजना से जुड़कर डिजिटल हो चुकी हैं।

मोबाइल ऐप से प्रक्रिया होगी सरल

ई-मंडी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए किसानों के लिये प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। किसानों को यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि वह मंडी आने से पहले मंडी में अपनी प्रवेश पर्ची खुद अपने मोबाइल से बना सकते हैं। एक बार प्रवेश पर्ची बन जाने पर बार-बार उन्हें अपना संपूर्ण डाटा मंडी में देने की जरूरत नहीं रहेगी। प्रवेश पर्ची बनने से किसान सीधे मंडी परिसर के नीलामी स्थलों पर जाकर अपनी कृषि उपज की नीलामी करा सकते हैं।

मोबाइल पर मिलेगी सभी जानकारी

उपज नीलामी की कार्यवाही की जानकारी किसानों को मोबाइल ऐप पर भी मिलेगी। उपज की तौल करने वालों को ई-मंडी योजना की ट्रेनिंग दी गई है और वे एंड्रॉयड मोबाइल पर की गई तौल का फाइनल वजन दर्ज करेंगे। साथ ही व्यापारी साथियों को भी भुगतान पत्रक बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ई-मंडी योजना में व्यापारी की आईडी पर रेडीमेड भुगतान पत्रक दिखेगा। व्यापारी को उनकी ओर से किसानों को किये जा रहे भुगतान की सिर्फ एंट्री करनी होगी। उधर, किसानों की ओर से मंडी में बेची जा रही उपज का रिकार्ड रियल टाइम ऑनलाइन होगा। किसानों को प्रवेश, अनुबंध, तौल और भुगतान के बाद उनके मोबाइल पर एसएमएस और व्हाट्सएप मैसेज भी मिलेगा। किसानों को यह भी पता चलेगा कि उनकी उपज किस व्यापारी ने कितने दाम पर खरीदी है।

एक साल में पांच किसानों को कस्टम हायरिंग केंद्र और 285 को मिला कृषि यंत्रों पर अनुदान

भोपाल। जागत गांव हमार

देश में अधिक से अधिक किसान कृषि यंत्रों का उपयोग कर अपनी आमदनी बढ़ सकें इसके लिए कृषि विभाग द्वारा अलग-अलग कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जाता है। उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग से किसानों की मजदूरों पर निर्भरता कम होती है और समय पर वे कृषि कार्य पूर्ण कर सकते हैं। इस कड़ी में एमपी के खरगोन जिले में बीते एक साल में कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जिले के 05 हितग्राहियों को कस्टम हायरिंग योजना एवं 285 हितग्राहियों को ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ दिया गया है।

कस्टम हायरिंग केंद्र पर कितना अनुदान मिलता है- कृषि अभियांत्रिकी खरगोन के अधिकारी द्वारा बताया गया कि कस्टम हायरिंग योजना के अंतर्गत 10 से 25 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर वास्तविक लागत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत बीते 01 वर्ष में जिले के 05 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। इस योजना से लाभान्वित होने वाले हितग्राही किसानों को किराए पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध करा रहे हैं। इससे किसानों को उन्नत कृषि यंत्रों का लाभ मिल रहा है और कस्टम हायरिंग वाले हितग्राही को रोजगार मिल रहा है।

कृषि यंत्र पर कितना अनुदान मिलता है?

मध्य प्रदेश में किसानों को ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतगत्त किसानों को उन्नत कृषि यंत्र खरीदने पर अनुदान दिया जाता है। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को कृषि यंत्र की कीमत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, जबकि अन्य कृषकों को 40 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ दिया जाता है। बीते 01 वर्ष में इस योजना के अंतर्गत जिले के 285 किसानों को लाभान्वित किया गया है।

धनिया, मेथी और लहसुन को सबसे अधिक मारता है पाला, रोगों के लक्षण और उपचार जानिए

भोपाल। अभी शीतलहर का दौर चल रहा है। इसे देखते हुए फसलों को बचाने की सलाह दी जाती है। मप्र में चल रही शीतलहर और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए फसलों को पाले के प्रकोप से बचाव के लिए किसान उद्यान विभाग की ओर से बताए गए उपायों का प्रयोग कर सकते हैं। जब पाला पड़ने की संभावना हो तो खेत में सिंचाई करनी चाहिए। नमीयुक्त जमीन में काफी देर तक गर्मी रहती है।

कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिल रही है और किसानों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही

एक साल में 1870 किसानों को ड्रिप-स्प्रिंकलर के लिए दी 6 करोड़ सब्सिडी

भोपाल। जागत गांव हमार

फसलों के अधिक उत्पादन के लिए समय-समय पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसानों की सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भरता कम करने एवं उन्हें अपने जरूरत के अनुसार सिंचाई की सुविधा सुलभ कराने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसमें किसानों को ड्रिप, स्प्रिंकलर, रेनगन और पम्प सेट आदि खरीदने के लिये अनुदान राशि दी जाती है। इसमें किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम के लिए अनुदान दिया जाता है।

कृषि विभाग खरगोन के उप संचालक एमएस सोलंकी ने बताया कि बीते 01 साल में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत खरगोन जिले के 1870 किसानों को स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई के लिए 06 करोड़ 14 लाख 57 हजार रुपए का अनुदान दिया गया है। इससे जिले के कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिल रही है और किसानों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही है।

किसानों को इन योजनाओं का भी मिला लाभ

उप संचालक सोलंकी ने बताया कि बीते 01 वर्ष में राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना के अंतर्गत जिले के किसानों को दलहनी, मोटा अनाज एवं व्यवसायिक फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए फसल प्रदर्शन, बीज वितरण, बीज उत्पादन एवं प्रशिक्षण का लाभ दिया गया है। इसके अंतर्गत बीते 01 वर्ष में जिले के 2759 किसानों को 02 करोड़ 38 लाख 53 हजार रुपए का अनुदान दिया गया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय तिलहन मिशन के अंतर्गत जिले के 01 हजार 37 किसानों को 51 लाख 17 हजार रुपए का अनुदान दिया गया है।

कृषि यंत्रों पर दिया गया 1 करोड़ 30 लाख रुपए का अनुदान

वहीं जिले में कृषि में यंत्रों के उपयोग को प्रोत्साहित करने एवं किसानों की मजदूरों पर निभज्रता कम करने के लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों को कृषि उपकरणों पर अनुदान दिया जाता है। बीते 01 वर्ष में जिले के 4,417 किसानों को हस्त एवं बैल चलित कृषि यंत्रों पर 01 करोड़ 30 लाख 40 हजार रुपए का अनुदान दिया गया है। इसी प्रकार बीते 1 वर्ष में जिले के 23 हजार 344 किसानों को स्वाईल हेल्थ कार्ड प्रदान किए गए हैं। इस कार्ड से किसानों को अपने खेत की मिट्टी में मौजूद मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के वास्तविक मात्रा का पता चल जाता है और उसी के अनुरूप वे फसलों में उर्वरक का उपयोग कर सकते हैं।

जैविक खाद का उपयोग फसल की गुणवत्ता को बढ़ाने में करता है मदद

किसानों के लिए बेहद लाभकारी है इस विदेशी सब्जी की खेती, प्रति एकड़ होगी तीन लाख रु. की कमाई

भोपाल। जागत गांव हमार

आइसबर्ग लेट्यूस, जिसे 'क्रिस्पहेड लेट्यूस' के नाम से भी जाना जाता है, सलाद के लिए उपयोग की जाने वाली एक लोकप्रिय पत्तेदार सब्जी है। यह न केवल स्वाद में खास है, बल्कि विटामिन और खनिजों से भरपूर होने के कारण स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। तेजी से बढ़ती मांग के कारण यह किसानों के लिए लाभदायक खेती का एक आकर्षक विकल्प बना गया है। यदि आप भी इस विदेशी सब्जी की खेती करना चाहते हैं, तो इसकी विशेषताओं और सही तकनीकों को जानना बेहद जरूरी है।

आइसबर्ग लेट्यूस की खेती के लिए ठंडी और समशीतोष्ण जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसकी खेती के लिए दिन का तापमान 15 से 20 डिसे. और रात का तापमान 10 से 15 डिसे. के बीच होना चाहिए। बहुत अधिक गर्मी या पाला इस फसल के लिए हानिकारक हो सकता है। इसकी खेती के लिए दोमट मिट्टी जिसमें जैविक पदार्थ की भरपूर मात्रा हो, सबसे अच्छी होती है। मिट्टी का पीएच स्तर 6.0 से 6.5 के बीच होना चाहिए। जल निकासी की उचित व्यवस्था भी जरूरी है, ताकि फसल को जलभराव की समस्या न हो।

बीज की बोवनी और तैयारी

आइसबर्ग लेट्यूस की खेती में बीज की बुवाई एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

बीज की चयन: उच्च गुणवत्ता वाले हाइब्रिड बीजों का चयन करें।

नर्सरी तैयार करना: बुवाई से पहले नर्सरी में बीज बोएं। इसके लिए जैविक खाद से समृद्ध मिट्टी का उपयोग करें। बीजों को लगभग 1 सेंटीमीटर की गहराई में बोया जाता है।

पौधों की रोपाई: बीज अंकुरित होने के बाद, जब पौधे 3 से 4 सप्ताह पुराने हो जाएं और 4 से 5 पत्ते निकल आएं, तो उन्हें मुख्य खेत में स्थानांतरित करें।

सिंचाई और खाद प्रबंधन

आइसबर्ग लेट्यूस की फसल को नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। हालांकि, जलभराव से बचना बेहद जरूरी है। ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग करना अधिक फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे जल की बचत होती है और पौधों को पर्याप्त नमी मिलती है। खाद प्रबंधन में जैविक खाद और नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का संतुलित उपयोग करें। पौधों की वृद्धि के समय नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस का सही अनुपात में उपयोग करें। जैविक खाद का उपयोग फसल की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करता है।

फसल संरक्षण

आइसबर्ग लेट्यूस की फसल को कीट और रोगों से बचाने के लिए नियमित निगरानी करें। आमतौर पर इस फसल में एफिड्स, थ्रिप्स और कटवर्म जैसे कीट लग सकते हैं। इनसे बचाव के लिए जैविक कीटनाशकों का उपयोग करें। रोगों में फ्यूजेरियम विल्ट और पाउडरी मिल्ड्यू प्रमुख हैं। इनसे बचने के लिए खेत में उचित वायु संचार और पौधों की सही दूरी का ध्यान रखें।

कटाई और भंडारण

आइसबर्ग लेट्यूस की कटाई तब की जाती है जब इसका सिर (हेड) पूरी तरह से विकसित हो जाए और सघन महसूस हो। कटाई के बाद इसे ठंडी जगह पर भंडारित करें। इसका भंडारण 0 से 2 डिसे. तापमान पर किया जा सकता है, जिससे यह अधिक समय तक ताजा बना रहता है।

लाभ और बाजार

आइसबर्ग लेट्यूस की मांग प्रमुख रूप से होटल, रेस्तरां और सुपरमार्केट में होती है। इसे सलाद, बर्गर और सैंडविच में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खेती किसानों के लिए अत्यधिक लाभदायक है। प्रति एकड़ खेती में लागत लगभग 40,000 से 50,000 रुपए आती है, जबकि 2 से 3 लाख रुपए तक की आय हो सकती है। यदि उचित प्रबंधन और विपणन किया जाए, तो मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है।

लाही और आरा मक्खी जैसे कीट लगने की संभावना सबसे अधिक

सरसों की फसल में लगने वाले प्रमुख कीटों की पहचान, उत्पादक जान लें सरल उपाय

भोपाल। जागत गांव हमार

सरसों की फसल में लाही और आरा मक्खी जैसे कीट उत्पादन को नुकसान पहुंचाते हैं। लाही कीट पत्तियों, तनों, और फलियों से रस चूसता है, जबकि आरा मक्खी पत्तियां काटकर क्षति पहुंचाती है। प्रबंधन के लिए पीले फंदे, नीम आधारित कीटनाशी और रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करें। समय पर पहचान और उपाय से नुकसान रोका जा सकता है। सरसों की फसल में कीटों का प्रकोप अक्सर उत्पादन और गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इसकी फसल में अगर कीटों को समय पर पहचान नहीं किया जाता है, तो किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में किसान समय पर सरसों की फसल में लगने वाले कीटों की पहचान कर सही प्रबंधन करना बेहद जरूरी है। बता दें कि सरसों की फसल में लाही और आरा मक्खी जैसे कीट लगने की संभावना सबसे अधिक होती है। इनसे बचाव के लिए जैविक और रासायनिक उपाय अपनाए जा सकते हैं।

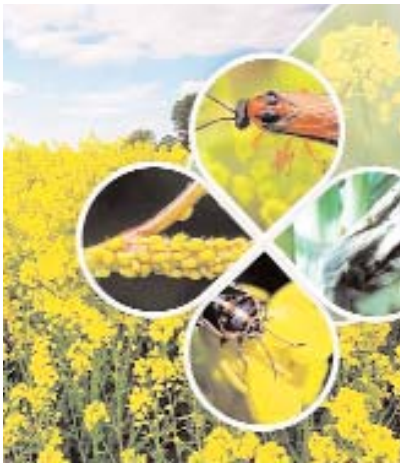

प्रमुख कीट की पहचान और प्रबंधन

लाही - लाही कीट पीला, हरा या काले भूरे रंग का मुलायम, पंखयुक्त या पंखहीन कीट होता है। इस कीट का वयस्क एवं शिशु कीट दोनों ही मुलायम पत्तियों, टहनियों, तनों, पुष्पक्रमों तथा फलियों से रस चुसते हैं। इसके आक्रांत पत्तियां मुड़ जाती है।

प्रबंधन: खेत में प्रति हेक्टेयर 10 पीला फंदा का प्रयोग करना चाहिए। नीम आधारित कीटनाशी एजाडिरेक्टन 1500 पीपीएम का 5 मिली. लीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करना चाहिए। प्रकोप अधिक होने पर रासायनिक कीटनाशी के रूप में ऑक्सीडेमेटान मिथाइल 25 ईसी एक मिली. प्रति लीटर पानी अथवा थायोमेथाक्साम 25 प्रतिशत डब्लूस जीस @1 ग्राम प्रति लीटर पानी या इमिडाक्लोप्रिड 8 प्रतिशत एसएल का 1 मिलीस प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए।

आरा मक्खी- वयस्क कीट नारंगी-पीले रंग तथा काले सिर वाले होते हैं। इसकी मादा का ओविपोजिटर आरी के समान होता है, इसलिए इसे आरा मक्खी कहते हैं। इसके पिल्लू पत्तियों को काटकर क्षति पहुंचाते हैं।

प्रबंधन:- नीम आधारित कीटनाशी एजाडिरेक्टिन 1500 पीपीएम का 5 मिलीस प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशियों में डायमेथोएट 30 प्रतिशत ईसी का मिलीस प्रति लीटर पानी अथवा क्लीनफॉस 25 प्रतिशत ईसद्ध का 1.5 मिली. की दर से पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करना चाहिए।

गेहूं और चना में कीट और रोगों से बचाव के लिए किसान करें इन दवाओं का छिड़काव

भोपाल। जागत गांव हमार

अभी मौसम हो रहे परिवर्तन के कारण रबी मौसम की प्रमुख फसलें गेहूं एवं चना में रोग एवं कीटों के प्रकोप होने की पूरी संभावना बनी हुई है। जिसको देखते हुए कृषि विकास विभाग के मैदानी अमले द्वारा कृषकों के खेतों का भ्रमण करके फसलों में आने वाली समस्याओं से रूबरू कराते हुए उनके बेहतर उपायों से किसानों को अवगत कराया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों द्वारा कृषकों को फसलों में आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी दी जा रही है और उनके बेहतर उपायों से अवगत कराया जा रहा है।

चने में लग सकता है उकठा एवं जड़-सड़न रोग- एमपी के सीहोर कृषि विभाग के मुताबिक इस अवस्था में मौसम में परिवर्तन जैसे दिन में न्यूनतम तापमान के कारण पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुचारू रूप से न होने के कारण चना फसल प्रभावित होने के साथ-साथ फसल के पौधे पीले पड़कर सूख रहे है। जिसके चलते फसल में आर्थिक नुकसान होने की पूरी संभावना है और साथ ही फसल में चने की सुंडी इल्ली के साथ-साथ उकटा व जड़-सड़न रोग के प्रकोप के कारण भी फसल सूख रही है।

कृषि विकास विभाग ने किसान भाइयों को सलाह दी है कि वे चना फसल की सुरक्षा के लिए इमामेक्टिन बेन्जोएट + प्रोफेनोफास 200 ग्राम प्रति एकड़ या क्लोरोइन्ट्रानिलीप्रोल + लेम्ब्डासाइलोथ्रिन 80 मिली/एकड़ के साथ फ्लूपायराक्साइड + पायरोक्लोरोस्ट्रोबिन 150 मिली/एकड़ या एजोक्सीस्ट्रोबिन +टेबूकोनोजोल 150 मिली/एकड़ के साथ एनपीके 19:19:19, 1 किग्रा/एकड़ से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

गेहूं में जड़ माहू एवं कटुआ इल्ली का नियंत्रण

कृषि विभाग ने बताया कि जिले की मुख्य फसल गेहूं में भी वतज़्मान समय में जड़ माहू कीट व कटुआ इल्ली का प्रकोप प्रारम्भिक अवस्था से ही फसल पर बना हुआ है जिसके कारण फसल पीली पड़ कर सूख रही है व इल्ली के प्रकोप के कारण फसल की वानस्पतिक वृद्धि व बालियां प्रभावित हो रही है। किसानों को सलाह है कि उक्त कीटों के निदान के लिए इमामेक्टिन बेन्जोएट + प्रोफेनोफास 200 ग्राम/एकड के साथ एनपीके 19:19:19, 1 किग्रा/ एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। साथ ही किसानों को सलाह है कि अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए सतत कृषि विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क में रहें।

ओएनजीसी के ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं बीज

अरंडी की खेती किसानों के लिए फायदेमंद राष्ट्रीय बीज निगम सस्ते में दे रहा बीज

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

राष्ट्रीय बीज निगम किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन अरंडी का हाइब्रिड आईसीएच-66 किस्म का बीज बेच रहा है। इसके बीज को आप ओएनजीसी के ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। यहां किसानों को कई अन्य प्रकार की सब्जियों, फलों और औषधीय फसलों के बीज आसानी से मिल जाएंगे।

भारत में किसान अब बागवानी फसलों के साथ-साथ औषधीय फसलों की भी खेती बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। इससे किसानों को अच्छी आमदनी हो रही है। ऐसे तो किसान कई तरह के औषधीय फसलों की खेती से अच्छी कमाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें अरंडी एक तरह की बेहतरीन जड़ी बूटी है। अरंडी को आम बोल चाल की भाषा में रेंडी भी कहा जाता है। इसके तेल की मांग मार्केट में बहुत है। इसके तेल का उपयोग कई तरह के रोगों के इलाज में किया जाता है। ऐसे में अगर आप भी औषधीय फसलों की खेती

करना चाहते हैं तो आप नीचे दी गई जानकारी की सहायता से अरंडी की हाइब्रिड किस्म आईसीएच-66 का बीज ऑनलाइन आसानी से अपने घर मंगवा सकते हैं।

अरंडी के किस्म की खासियत- आईसीएच-66 अरंडी की एक खास किस्म है। ये एक मध्यम अवधि वाली संकर किस्म है। इसकी पहली तुड़ाई 94-97 दिनों में तैयार हो जाता है। इसकी औसत बीज उपज 1450-1750 किग्रा प्रति हेक्टेयर है। ये किस्म फ्यूजेरियम विल्ट, मक्रोफोमिना रूट रॉट और लीफहॉपर के लिए प्रतिरोधी है। इस किस्म की खेती भारत में सबसे अधिक वर्षा आधारित वाली क्षेत्रों में होती है।

अरंडी के किस्म की कीमत

अगर आप अरंडी की खेती करना चाहते हैं तो आईसीएच-66 किस्म के 2 किलो के पैकेट का बीज फिलहाल 28 फीसदी छूट के साथ 970 रुपये में राष्ट्रीय बीज निगम की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। इसे खरीद कर आप आसानी से अरंडी की खेती कर बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं।

अरंडी की खेती के लिए मिट्टी

अरंडी की खेती किसी भी जमीन पर भी की जा सकती है। इसके लिए मिट्टी का पीएच मान 6 होना चाहिए। साथ ही इसके खेत में जल निकासी की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। आद्र्र और शुष्क तापमान में इसके पौधे तेजी के साथ ग्रोथ करते हैं। इसलिए जहां पर अधिक गर्मी पड़ती है, वहां किसानों के लिए अरंडी की खेती करना लाभदायक साबित हो सकता है।

अरंडी के तेल के जानिए फायदे

अरंडी एक औषधीय फसल है। इसका तेल बहुत महंगा बिकता है। अगर किसान अरंडी की खेती करते हैं, तो अच्छी कमाई कर सकते हैं। अरंडी का पौधा देखने में झाड़ी की तरह लगता है। इसके बीज से तेल निकाला जाता है। खास बात यह है कि अरंडी के तेल से कई तरह की औषधीय दवाइयां बनाई जाती हैं। साथ ही साबुन भी बनाया जाता है।

यहां से मंगवाएं अरंडी के बीज

राष्ट्रीय बीज निगम किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन अरंडी का हाइब्रिड आईसीएच-66 किस्म का बीज बेच रहा है। इसके बीज को आप ओएनजीसी के ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। यहां किसानों को कई अन्य प्रकार की सब्जियों, फलों और औषधीय फसलों के बीज आसानी से मिल जाएंगे। किसान इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर पर डिलीवरी करवा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसान वेबसाइट के इस लिंक पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं।

जय जवान-जय किसान-जय विज्ञान में जुड़ा जय अनुसंधान

मुख्यमंत्री ने किया राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय विज्ञान और परंपरा के गहरे संबंध हैं। भारत ने हमेशा अपने नेतृत्व से विज्ञान और नवाचार को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच ने भारतीय विज्ञान और अनुसंधान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान, जय किसान का आह्वान कर भारत को एक नई ऊर्जा दी। इस नारे ने न केवल भारत की रक्षा और कृषि को मजबूत किया, बल्कि राष्ट्र को आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित भी किया। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने इस कड़ी में जय विज्ञान को जोड़ा, जो भारत की वैज्ञानिक सोच और उपलब्धियों को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस श्रृंखला में जय अनुसंधान जोड़ते हुए विज्ञान और नवाचार को एक नई दिशा दी है। कोविड-19 महामारी के दौरान मात्र एक वर्ष में स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण करना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। यह उपलब्धि भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य और नेतृत्व की कुशलता को प्रदर्शित करती है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. वाजपेयी के समय में हुए परमाणु परीक्षण और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई वैज्ञानिक प्रगति, दोनों ही यह दिखाते हैं कि भारत ने हर चुनौती को अवसर में बदलकर दुनिया के सामने अपनी योग्यता और क्षमता को सिद्ध किया है। मुख्यमंत्री रवींद्र भवन में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ कर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस को बाल प्रतिभाओं के विकास का बेहतरीन मंच बताया। इस अवसर पर सीएम ने उज्जैन जिले के डोंगला में स्थापित वराह मिहिर खगोलीय वेधशाला में हुए नवीनीकरण कार्य एवं नए उपकरणों के साथ ऑटोमेशन कार्य का वर्चुअल शुभारंभ किया। उन्होंने वीर भारत न्यास के रिसर्च जर्नल युगयुगीन भारत का पुरोवाक का विमोचन किया, साथ ही वीर भारत न्यास द्वारा बनाई गई महादेव फिल्म सीरीज का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह का वीडियो संदेश भी प्रसारित किया गया। वीडियो संदेश में केन्द्रीय मंत्री ने बच्चों को श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने की प्रेरणा देकर उनका उत्साहवर्धन किया।

सीएम ने पचमढ़ी में प्राकृतिक रेशमी वस्त्रों की प्रदर्शनी देखी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नर्मदापुरम जिले में स्थित पर्यटन केंद्र पचमढ़ी में प्राकृतिक रेशमी वस्त्रों की विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शनी प्राकृत- द गिफ्ट ऑफ नेच्यूरल का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने वस्त्रों के निर्माण,विक्रय व्यवस्था आदि की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में पचमढ़ी न केवल अप्रतिम सुंदरता और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि प्रदेश के वस्त्र शिल्पियों के बनाए कलात्मक वस्त्रों के विक्रय की दृष्टि से भी देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अनूठी प्रदर्शनी के लिए एमपी सिल्क फेडरेशन के समस्त टीम सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

जागत गांव हमार, सलाहकार मंडल

1. **प्रो. डा. केआर मौर्य, पूर्व कुलपति,** राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसासमस्तीपुर (बिहार) एवं महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान) ईमेल-kuber.ram@gmail.com, मोबा- 7985680406
2. **प्रो. डा. गैब्रियल लाल, प्रोफेसर,** आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग सैम हिंगिन बॉटम यूनिवर्सिटी आफएग्रीकल्चर, टेक्नालोजी एंड साइंसेज, प्रयागराज, उप्र। ईमेल- द्दुद्बद्धiyal.lal @shiats.edu.in, मोबा- 7052657380
3. **डा. वीरेन्द्र कुमार,** प्रोफेसर एंड हेड, पौध रोग विज्ञान विभाग, डा. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय परिसर ढोली, मुजफ्फरपुर बिहार। ईमेल- birendraray@gmail.com मोबा- 8210231304
4. **डा. नरेश चन्द्र गुप्ता, वैज्ञानिक,** मृदा विज्ञान, कृषि महाविद्यालय बिरसा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कॉके, रॉची झारखण्ड। ईमेल- ncgupt-abau@gmail.com, मोबा- 8789708210
5. **डा. देवेंद्र पाटिल, वैज्ञानिक** (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, सीहोर (मध्यप्रदेश) सेवनिया, इछावर, सिहोर (मप्र) ईमेल- dpatil889@gmail.com, मोबा- 8827176184
6. **डा. आशुतोष कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर,** एग्री विजनेस मैनेजमेंटकृषि अर्थशास्त्र विभाग, एकेएस,विश्वविद्यालय, सतना, मप्र ईमेल- kumar.ashu777@gmail.com, मोबा- 8840014901
7. **डा. बिनीता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर** आनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग एकेएस विश्वविद्यालय, सतना, मप्र ईमेल- singhvineeta123@gmail.com, मोबा- 8840028144
8. **डा. आरके शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर,** परिजीवी विज्ञान विभाग, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, बिहार। ईमेल- drrksharmabvc@gmail.com, मोबा- 9430202793
9. **डा. दीपक कुमार, सहायक प्राध्यापक,** मृदा एवं जल संरक्षण अभियंत्रिकी विभाग, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर, उत्तराखण्ड। ईमेल- deepak.swce.cot.gbpuat@gmail.com, मोबा- 7817889836
10. **डा. भारती उपाध्याय, विषय वस्तु विशेषज्ञ** (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, विरौली, समस्तीपुर, बिहार। ईमेल-bharati.upadhya@rpcau.ac.in, मोबा- 8473947670
11. **रोमा वर्मा,** सब्जी विज्ञान विभाग महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं् वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़। ईमेल- romaverma35371@gmail.com, मोबा- 6267535371

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। **संपादकः** अजय कुमार द्विवेदी, **स्थानीय संपादकः अरविंद मिश्रा, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)